• वर्ष : 05 • अंक : 03 • अगस्त 2026 • हिन्दी मासिक पत्रिका ₹ 40/-

RNI : CHHHIN 2022/86325

स्वतंत्र बोल

www.swatantrabol.com

परिवहन विभाग बना वसूली का अड्डा!

सेवा सेतु

जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं **त्वरित, पारदर्शी और आसान**

520

शासकीय सेवाएं

घर बैठे, एक क्लिक में

नागरिकों के लिए सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं

95.9%

आवेदनों का निराकरण

- **38 लाख+** आवेदन
- **16,700+** सेवा केंद्र
- **36 विभाग** एक मंच पर

प्रमुख सेवाएं

- ✓ **जाति प्रमाण** पत्र
- ✓ **आय प्रमाण** पत्र
- ✓ **निवास प्रमाण** पत्र
- ✓ **विवाह प्रमाण** पत्र
- ✓ **राशन कार्ड** सेवाएं
- ✓ **पेंशन** योजनाएं
- ✓ नाम **परिवर्तन सेवा**
- ✓ व्यापार **लाइसेंस**

अधिक जानकारी हेतु स्कैन करें

जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार

sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400

RNI : CHHHIN 2022/86325

स्वतंत्र बोल

www.swatantrabol.com

वर्ष : 05, अंक : 03, अगस्त 2026

प्रेरणास्त्रोत
स्व. जीवन गिरि गोस्वामी

संपादक
राहुल गिरि गोस्वामी

कानूनी सलाहकार
आनंद मोहन तिवारी
दिनेश मिश्रा

प्रचार-प्रसार-विज्ञापन
शेखर सागर

ले-आउट/डिजाइन
द्वारिका प्रसाद साहू

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक
राहुल गिरि गोस्वामी द्वारा
डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने
टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001 से प्रकाशित
एवं सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001 से मुद्रित।
सम्पादक - राहुल गिरि गोस्वामी

रजिस्टर्ड कार्यालय
डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने
टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001
Email : Bolswatantra@gmail.com
Phone : 9754374333

(समस्त न्यायालीन प्रकरणों के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र रायपुर होगा।)

पेपर लीक से हंगामा, युवाओं में ... 03

परिवहन विभाग बना वसूली का अड्डा, पैसे दो-... 06

बिलाई माता मंदिर, कांकेर महल ... 08

मेरी बेटी- मेरा अभिमान: बालिकाओ के स्कूलों में बनेगा 286 करोड़ से शौचालय 12

आत्मनिर्भर नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़ : महिला... 14

न हिंदू न मुसलमान बल्कि बचपन और... 17

गायों के संवर्धन के लिए शुरू हुआ 'सुरभि... 20

दिमागी नक्सल: विरोध की राजनीति का नया... 24

संपादकीय

नौकरी और परीक्षाओ में हो जीरो टॉलरेंस, ताकि युवाओ का भविष्य बर्बाद ना हो

सरकारी नौकरियों और परीक्षाओ में जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा, वह आम लोगो के लिए बेहद चिंताजनक है। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे उच्च शिक्षित बेरोजगार युवाओ के भविष्य से खिलवाड़ कर नौकरियां बेचीं जा रही, चोर दरवाजे से राजनेताओ के बीटा बेटियों और रिश्तेदारों को उपकृत किया जा रहा, परीक्षा के पहले पेपर लाखो रूपए लेकर बेचा जा रहा, यह बेहद शर्मनाक है। सरकारी नौकरी की तैयारी में युवाओ की जवानी चीन जा रही, मेहनतकश युवाओ के सपने छीन जा रहे और रसूखदार साधन संपन्न लोग पैसे के दम पर उनका हक़ छीन रहे। चोर से दरवाजे से नौकरी पाया व्यक्ति क्या सिस्टम और समाज के साथ न्याय कर पायेगा? जिसने लाखो करोडो देकर पैसे दम नौकरी हासिल की हो, उसका ध्यान शुरुआत से लगाए गए पैसे की वापसी पर रहेगा और पूरी उम्र भर इसी डर में रहेगा कि कही कोई उसकी नौकरी न छीन लें। ऐसे में सरकार चाहे राज्य की हो केंद्र की उन्हें नौकरी में फर्जीवाड़ा को रोकने कड़े कदम उठाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अधिकांश विश्वविद्यालयो में हो रही भर्ती में बैकडोर से नियमो का उल्लंघन कर नियुक्तियां की जा रही, मनमाफिक बोली लग रही और जाँच के नाम पर लीपापोती कर युवाओ का भविष्य ख़राब किया जा रहा है।

– राहुल गिरी गोस्वामी

पेपर लीक से हंगामा, युवाओं में आक्रोश और धमेन्द्र प्रधान का इस्तीफा...

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई. प्रदर्शन स्थल की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं. वहीं, CJP के प्रदर्शनकारी जब रेल भवन पहुंचे तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है.

चश्मदीदों के मुताबिक, सैकड़ों छात्र और युवा प्रदर्शनकारी मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर जमा हुए थे. वहां से वो मार्च करते हुए जंतर-मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां CJP का धरना स्थल है. इसमें बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल थीं.

जंतर-मंतर की ओर कदम बढ़ाते हुए इन युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का तेवर देख पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद था. पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की.

हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी

जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मौके पर भगदड़ मच गई. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई छात्र नेताओं और युवाओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में भरकर वहां से ले गई.

इस घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और लाठीचार्ज का मंजर देखा जा सकता हैं.

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी आज बंद कर दिए गए हैं. इनमें जनपथ और पटेल चौक शामिल है. कई मेट्रो स्टेशनों से भारी भीड़ के विजुअल्स सामने आ रहे हैं।

नीट प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर चली पेलेट गन

देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर इस समय विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी इसे लेकर प्रदर्शन जारी है. 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 'चलो संसद' मार्च का ऐलान किया गया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई थी. प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगे थे. अब इस मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है. रैपिड एक्शन फोर्स ने अपने जवानों पर लगे जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, आरएएफ ने दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शनों के दौरान अपने जवानों की ओर से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पैलेट गन चलाने के आरोपों की जांच शुरू की है. यह कदम उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया है, जिनमें घायलों की गवाही और मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर दावा किया गया था कि 20 जुलाई को हुए मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पैलेट गन से चोटें आई थीं.

रिपोर्ट्स में इसे राजधानी दिल्ली में किसी विरोध-प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल की एक रेयर घटना बताया गया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है. पुलिस का कहना है कि वह भीड़ को कंट्रोल करने के लिए न तो पैलेट गन रखती है और न ही इसका इस्तेमाल करती है.

घटनाओं का पूरा क्रम तैयार करने के निर्देश

अधिकारियों के मुताबिक, रैपिड एक्शन फोर्स जिस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तहत काम करती है, उसने RAF के इंस्पेक्टर जनरल को 20 जुलाई के ऑपरेशन के दौरान हुई घटनाओं के पूरे क्रम को दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया है. इस वेरिफिकेशन के दौरान दोनों पक्षों से जुड़ी घटनाओं की जांच की जाएगी. इसमें प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आरएएफ की ओर से की गई कार्रवाई के साथ उन घटनाओं को भी देखा जाएगा, जिनमें आरएएफ के जवानों पर कथित तौर पर हमला किया गया था. 'चलो संसद' मार्च के दौरान बाद में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी.

CRPF अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभी तक औपचारिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश नहीं दिए गए हैं. फिलहाल वेरिफिकेशन के जरिए पहले पूरे मामले के तथ्यों का पता लगाया जाएगा. इसके बाद फैसला होगा कि मामले में औपचारिक जांच की जरूरत है या नहीं.

वीडियो और तस्वीरों की भी होगी जांच

अधिकारियों के अनुसार, RAF ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो और तस्वीरों का भी संज्ञान लिया है. इनमें आरएएफ की नीली कैमोफ्लाज वर्दी में जवान दिखाई दे रहे हैं. इन वीडियो में भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान आरएएफ के जवान लाठी और हथियार लिए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, कुछ अन्य वीडियो में आरएएफ के जवानों को प्रदर्शनकारियों से घिरा हुआ और उन पर हमला होते हुए भी देखा जा सकता है. इन वीडियो और तस्वीरों की भी वेरिफिकेशन के दौरान जांच की जाएगी।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा...

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है. NEET-UG परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देशभर में जारी विवाद और जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने यह फैसला लिया. धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक इसका ऐलान किया और इस्तीफा देने की वजह भी बताई.

अपने चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले चार दशक से अधिक समय से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं. उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, '3 मई 2026 को आयोजित NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की. मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया और अगले साल से NEET को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित करने की घोषणा की गई. '

धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और सुचारु रूप से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी. इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई. 16 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों को सफलता मिली, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा.

अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है. उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके. इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया.

चिट्ठी के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आगे भी वह भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे।

परिवहन विभाग बना वसूली का अड्डा, पैसे दो- पोस्टिंग लो!

स्वतंत्र बोल डेस्क

भ्रष्ट अफसरों के लिए छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित जगह बना हुआ है। यहाँ के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार अब आम बात हो चुकी है, या यूं कहे कि भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं रह रह गया, शिष्टाचार बन गया है। परिवहन विभाग में स्थिति ऐसा है कि पैसे दो- मनमाफिक जगहों में पोस्टिंग लो। दरअसल परिवहन विभाग को कमाई वाला विभाग मना जाता है, यहाँ नियुक्ति से लेकर कुर्सियों में बैठने के लिए कर्मचारी लालायित रहते है। विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी भी करोडो के आसामी निकलता है। ऐसे में प्रमुख पदों पर बैठे लोगो के द्वारा जिस तरह इसे सरंक्षण दिया जा रहा, वह चिंताजनक है।

छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग के मंत्री है केदार कश्यप.. वरिष्ठ बीजेपी नेता है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके है। मौजूदा समय में परिवहन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और सहकारिता विभाग उनके पास है। उनके ओएसडी रहे प्रदीप वैद ने विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया है। प्रदीप वैद मूलतः राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) है, प्रतिनियुक्ति पर उन्हें मंत्री अपना ओएसडी बनाया था। बैद परिवहन विभाग में अधिकारियो और कर्मचारियों के पोस्टिंग के नाम पर मंत्री के सरंक्षण में जमकर वसूली किया। इस विभाग में सचिव सह आयुक्त के पद पर साल 2005 बैच के आईएएस एस प्रकाश है, पूर्ववर्ती कॉंग्रेस्सकी सरकार

में अच्छे मलाईदार विभागों में पोस्टेड रहे तो अपर आयुक्त (एटीसी) के पद पर पुलिस विभाग में डीआईजी डी. रविशंकर है। रविशंकर पूर्व में परिवहन विभाग में उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त के पदों में रहने का अनुभव है। वे जशपुर में एसपी रहे, उसी कनेक्शन ने उन्हें एटीसी बनाने में संभवतः मदद की है।

निजी होटल में वसूली

प्रदीप बैद की पोस्टिंग मंत्री केदार कश्यप के निज स्थापना में थी, वे मंत्री बंगले में विभागीय काम संभालते थे, पर विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों से वसूली करने वे होटलो का सहारा लेते थे। परिवहन विभाग में आरक्षक, हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को मनमाफिक पोस्टिंग देने के लिए उनसे लाखों करोडों रुपये की वसूली नवा एक महंगे होटल में की गई। एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने इसका खबर भी प्रकाशित किया तो पैसे देने वालो ने वीडियो बना लिया। दरअसल विभाग के मैदानी अमला

में हर छह महीने में चेक पोस्ट, बरियर में तैनात कर्मियों का तबादला किया जाता रहा है। साल 2026 में ऐसे कर्मियों का ट्रांसफर मार्च के अंतिम सप्ताह में होना था, पर नहीं हो पाया। प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग में बैन होने पर मुख्यमंत्री के समन्वय में ही जरुरी होने पर तबादला हो रहा है ऐसे में फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा गया, पर बैद द्वारा लाखो करोडो रुपये वसूलने की शिकायते मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंची तो फाइल रोक दी गई। फाइल करीब दो महीने रुकी रही, और 06 जून को आदेश जारी हुआ जिसमे 46 परिवहन निरीक्षक, 50 परिवहन उपनिरीक्षक, 35 हवलदार और 18 आरक्षकों समेत कुल 165 कर्मियों का तबादला सूची जारी हुआ तो बवाल मच गया। मंत्री केदार कश्यप और ओएसडी प्रदीप बैद द्वारा भेजे गए अधिकांश नामो की छटनी हो चुकी थी, और नए नामो को ट्रांसफर लिस्ट में शामिल किया गया था।

बैद गायब, मंत्री केदार ने किया बचाव

परिवहन में जारी भ्रष्टाचार और वसूली की खबरे स्वतंत्र बोल की वेबसाइट में प्रकाशित हुई तो हड़कम्प मच गया। प्रदीप बैद द्वारा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और पर रायता फ़ैल चूका था। ऐसे में बैद ने कुछ दिनों के लिए मंत्री के नवा रायपुर स्थित बंगले जाना छोड़ दिया और अपना फोन भी बंद कर दिया था, उसके बाद भी मंत्री केदार कश्यप बैद के बचाव में थे। वे किसी भी प्रकार की कार्यावाही, जाँच के पक्ष में नहीं थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे

सवाल पूछने पर वे सवालकर्ता से प्रमाण मांगने लगे थे। बाद में प्रदीप बैद को हटाया गया और उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त आयुक्त बनाया गया।

केदार के विभाग में रविकांत मिश्रा का दखल !

परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ सहित अन्य दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री अपने किसी विश्वस्त मंत्री को देते है या स्वयं अपने पास रखते है। साल 2023 में विष्णुदेव से के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह विभाग मुख्यमंत्री के पास था। ऐसे में इस विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति सीएमओ से होती थी। अगस्त 2025 में मंत्रियो के विभागों में फेरबदल के बाद विभाग केदार कश्यप को दिया गया। मंत्री कश्यप को विभाग को समझने में दो से तीन महीना लगा और उसी दौरान महानदी और इंद्रावती में बैठे अधिकारियो ने बड़ा खेल भी किया है। विभागीय जानकारी अनुसार इस विभाग में नियंत्रण मुख्यमंत्री के ओएसडी रविकांत मिश्रा का रहा है। मौजूदा समय में विभागीय मंत्री केदार कश्यप है पर रविकांत मिश्रा का दखल अब भी बना हुआ है। ओएसडी रहे प्रदीप बैद की छुट्टी के बाद डिप्टी कलेक्टर दुष्यत रायस्ते को केदार कश्यप का ओएसडी बनाया गया है और वे परिवहन विभाग का काम संभल रहे है, पर प्रदीप की छुट्टी होने के बाद भर्राशाही में रोक नहीं लगा है। सिस्टम अपना काम कर रहा है।

बिलाई माता मंदिर, कांकेर महल और रुद्रेश्वर महादेव की कृपा...

स्वतंत्र बोल- डेस्क

छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला, जो पहले मध्य प्रदेश के रायपुर जिले का हिस्सा था, देश की सबसे पुरानी नगरपालिकाओं में से एक है। यह जिला पूर्व में ओडिशा राज्य और पश्चिम में दुर्ग जिले से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र समृद्ध वनस्पति और जीव-जंतुओं से परिपूर्ण है और यहाँ कई वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनमें कुछ सबसे अनोखे पेड़-पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं। यहाँ कई झरने भी हैं जो मानसून के दौरान पूरी तरह खिल उठते हैं, जिससे यह जगह घूमने के लिए एक बेहतरीन स्थान बन जाती है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, यहाँ कई धार्मिक स्थल भी हैं जो जिले को और भी शांत बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए, धमतरी में घूमने लायक पर्यटन स्थलों की सूची नीचे दी गई है, ताकि आप अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकें।

बिलाई माता मंदिर

धमतरी में स्थित बिलाई माता मंदिर को विंध्यवासिनी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह जिले के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर शहर के केंद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप आसानी से बस ले सकते हैं। मंदिर की वास्तुकला सरल है और इसका प्रवेश द्वार एक विशाल द्वार है; अंदर प्रवेश करते ही आपको एक बड़ा त्रिशूल और मंदिर के ठीक बाहर एक शेर की मूर्ति दिखाई देगी। मंदिर में कुछ स्थान हैं जहाँ आप परिक्रमा कर सकते हैं या बैठकर ध्यान या प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक घंटी लटकी हुई है जिसे आप बजा सकते हैं और अंदर आपको नारंगी रंग का मंदिर दिखाई देगा जो साड़ी से लिपटा हुआ है। इस क्षेत्र के लोग इस मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं।

सिहावा

धमतरी में कई तीर्थ स्थल हैं, जिनमें सिहावा जिले का सबसे लोकप्रिय पूजा स्थल है। धमतरी के केंद्र के काफी करीब स्थित सिहावा महानदी नदी के किनारे बसा है। यह तीर्थ स्थल हरे-भरे जंगलों और मनोरम पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में कई दर्शनीय स्थल हैं जैसे करबेश्वर मंदिर, गणेश घाट, दंतेश्वरी गुफा, महामाई मंदिर और अमृत कुंड। यहां ह्लींगी हाथी खोट नाम का एक आश्रम भी है, जहां आप शांति से ध्यान कर सकते हैं। धमतरी में सिहावा अवश्य देखने योग्य स्थान है।

रुद्री

धमतरी में रुद्री का ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि यह स्थान प्राचीन काल में रुद्र देव के शासनकाल के दौरान कांकेर राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और महानदी नदी के किनारे स्थित है, जहां रुद्रेश्वर मंदिर प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यदि आप इस स्थान के इतिहास के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आसपास के मंदिरों का दर्शन करें और स्थानीय लोगों से बात करके रुद्री और इसके महत्व के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।

गैंगरेल बांध

धमतरी के केंद्र से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, गंगरेल बांध महानदी नदी पर बना एक विशाल बांध है। यह बांध रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा बांध है । यह बांध स्थानीय लोगों, विशेष रूप से किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, जिन्हें साल भर सिंचाई की सुविधा मिलती है; इससे किसान हर साल दो अलग-अलग फसलें उगा सकते हैं और यह उनके व्यवसाय के लिए बहुत सहायक है। गंगरेल बांध भिलाई में स्थित भिलाई स्टील प्लांट के लिए पानी का मुख्य स्रोत होने के साथ-साथ बिजली का भी मुख्य स्रोत है; इस बांध की जलविद्युत आपूर्ति

करने की क्षमता 10 मेगावाट है।

सीतानाडी वन्यजीव अभयारण्य

धमतरी जिले में स्थित सीतानंदी वन्यजीव अभ्यारण्य आसपास के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है; यह देश के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों में से भी एक है, जहाँ कुछ सबसे लुप्तप्राय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सीतानंदी वन्यजीव अभ्यारण्य हरे-भरे जंगलों से घिरा हुआ है और इसमें साल, बांस और सागौन जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। इसके अलावा, यहाँ मनमोहक सुगंध वाले रंग-बिरंगे फूल भी खिले हुए हैं। आप यहाँ बाघ, तेंदुए जैसे जानवरों के साथ-साथ सर्दियों में प्रजनन के लिए आने वाले स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। वन्यजीवों में रुचि रखने वाले बच्चों और वयस्कों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है।

मदमसिल्ली बांध

महानदी नदी की एक सहायक नदी पर स्थित, धामतरी में मदमसिल्ली बांध है, जिसे मुरुमसिल्ली बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध धामतरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। मदमसिल्ली बांध का निर्माण 1914 से 1923 के बीच हुआ था। यह एशिया का पहला बांध है जिसमें साइफन स्पिलवे (पानी का बहाव रोकने वाला मार्ग) है, इसलिए इसकी वास्तुकला की लोग बहुत सराहना करते हैं। आप धामतरी से कुकरेल जाने वाली सड़क से इस बांध तक पहुँच सकते हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रीपेड टैक्सियाँ भी उपलब्ध हैं।

अंगारमोती मंदिर

महानदी नदी के किनारे गंगरेल बांध के काफी करीब

अंगारमोती मंदिर स्थित है। यह एक बहुत ही सरल मंदिर है, जिसमें मुख्य रूप से दुर्गा देवी की प्रतिमा है, साथ ही अन्य हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यह एक अत्यंत शांत और सरल तीर्थस्थल है, जहां हर व्यक्ति को प्रार्थना करने और मंदिर के सामने कुछ क्षण बिताने का अवसर मिलता है। मंदिर से गंगरेल बांध का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। देश भर से बहुत से लोग अंगारमोती मंदिर में प्रार्थना करने और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं।

रुद्रेश्वर महादेव मंदिर

धमतरी में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जो जीवन के हर क्षेत्र से आने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा अत्यधिक श्रद्धापूर्वक देखा जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा रुद्र देव के शासनकाल में हुआ था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। रुद्रेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और स्थानीय लोग इसका बहुत सम्मान करते हैं, जो नियमित रूप से मंदिर में अपनी प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर की वास्तुकला सरल है और इसे पारंपरिक हिंदू वास्तुकला शैली में बनाया गया है। शिवरात्रि जैसे शुभ अवसरों को यहां बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

कांकेर महल

धमतरी के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक कंकर महल है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में शाही परिवार के निवास के रूप में किया गया था। यह महल राधा निवास बगीचा के नाम से भी जाना जाता था और अंग्रेजों के जाने के बाद, इसे पर्यटकों के ठहरने के लिए एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया। महल के अंदर का फर्नीचर, छत, दीवारें और अन्य चीजें प्राचीन हैं, जो किसी शाही महल में रहने का अनुभव कराती हैं। इस महल का दौरा पूरे साल किया जा सकता है और आप आधुनिक युग के पुराने समय का अनुभव करने के लिए कुछ दिनों तक यहां ठहर सकते हैं।

स्वामी संदीपानन्द ध्यान केंद्र

धमतरी में स्थित स्वामी संदीपानंद ध्यान केंद्र शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक शांत स्थान है। यह केंद्र योग और ध्यान के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसका निर्माण लोगों को ध्यान और योग तकनीकों का अभ्यास करने के लिए एक स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि वे रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकें। यहां आकर आप घंटों ध्यान कर सकते हैं या दूसरों से ध्यान करना सीख सकते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं, उनके लिए सुबह और शाम को नियमित योग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। यदि आप शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो अपनी यात्रा के दौरान मन को शांत करने के लिए इस स्थान पर अवश्य जाएं।

उपलब्धि : छत्तीसगढ़ को 'GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड'

छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में 'GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की गरिमामयी उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया गया। GeM के एक दशक पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समारोह की थीम 'GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities' रही।

राज्य सरकारों के लिए निर्धारित 'प्रीमियर अवार्ड्स - स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन' श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार GeM के प्रभावी उपयोग तथा इसके माध्यम से शासकीय खरीदी के मूल्य और मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रदान किया गया है।

खुली प्रतिस्पर्धा से 130 करोड़ रुपए की बचत

GeM प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन को 130 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह बचत विभागों द्वारा खरीदी के लिए अनुमानित लागत और खुली प्रतिस्पर्धी बोली के बाद प्राप्त वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से हुई है।

GeM की खुली बोली प्रक्रिया, मानकीकृत विनिर्देश और प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल एवं ऑडिट योग्य रिकॉर्ड शासकीय खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीदी के माध्यम से राज्य शासन को कुल 235 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

खरीदी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित जांच और निगरानी व्यवस्था लागू है। साथ ही निविदा की शर्तों एवं तकनीकी विनिर्देशों की नियमित समीक्षा की जाती है, जिससे खरीदी की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बनी रहे।

GeM से खरीदी में 113 प्रतिशत की वृद्धि

छत्तीसगढ़ में GeM के माध्यम से शासकीय खरीदी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 3,935 करोड़ रुपए पहुंच गई। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत की वृद्धि है।

राज्य शासन द्वारा विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीदी को एक साझा एवं पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के सुनियोजित प्रयासों से यह वृद्धि संभव हुई है। इससे अधिकाधिक शासकीय खरीदी खुली प्रतिस्पर्धा के दायरे में आई है और प्रत्येक लेन-देन में प्रतिस्पर्धी दर निर्धारण तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

सूक्ष्म व लघु उद्यमों को 1,800 करोड़ रुपए के ऑर्डर

GeM के व्यापक उपयोग से शासकीय खरीदी में छोटे उद्यमियों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) से खरीदी 61 प्रतिशत बढ़कर 1,800 करोड़ रुपए हो गई। यह निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से काफी अधिक है।

राज्य के प्राथमिकता वाले उद्यमी वर्गों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। महिला उद्यमियों से खरीदी में 97 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदी में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं स्टार्टअप से खरीदी में सर्वाधिक 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मेरी बेटी- मेरा अभिमानः बालिकाओ के स्कूलों में बनेगा 286 करोड़ से शौचालय

स्वतंत्र बोल- डेस्क

छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों के लिए मेरी बेटी मेरा अभिमान योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदेश में बालिकाओ को स्कूलों में प्रसाधन नहीं होने पर, उनकी परेशानियों को दूर दृढ़ संकल्पित है। मेरी बेटी मेरा अभिमान योजना अंतर्गत प्रदेश भर 6671 शौचालय बनाये जायेंगे। इस पर सर्कार करीब 286 करोड रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री साय ने महानदी भवन नवा रायपुर में मीडिया को जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि मेरी बेटी मेरा अभिमान अंतर्गत 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शौचालय की लागत 4.30 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपए की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे, जिनकी प्रति इकाई लागत 6 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त 18.22 करोड़ रुपए की लागत से 549 मुक्तिधामों का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी प्रति इकाई लागत 3.32 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद अथवा डिफंक्ट बोरवेलों में 52.14 करोड़ रुपए की लागत से सैंड फिल्टर एवं रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। प्रति इकाई लागत लगभग 52 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इससे भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत कर शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

ग्रामीण विकास व रोजगार का सबसे बड़ा अभियान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। योजना के अंतर्गत सभी विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति से किया जाएगा तथा मजदूरी की दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत-2047' के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो

ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यों के लिए राज्य में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। भारत सरकार से योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

किसानों व श्रमिकों का रखा गया विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का संतुलित ध्यान रखा गया है। कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे खेती और रोजगार दोनों प्रभावित न हों।

विकास कार्यों से बदलेगी गांवों की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 318 प्रकार के कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनमें 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण अधोसंरचना विकास कार्य, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य तथा 35 प्रकार के जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भू-जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं ग्रामीण अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, प्रयोगशाला, किचन शेड, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुक्तिधाम और पशु चिकित्सालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आजीविका संवर्धन के अंतर्गत ग्रामीण हाट-बाजार, कृषि उपज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मत्स्य पालन तथा पशुपालन से संबंधित अधोसंरचना विकसित की जाएगी। वहीं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़ एवं चक्रवात आश्रय, ड्रेनेज, तटबंध, जंगलों में आग की रोकथाम तथा प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्राम पंचायत कार्ययोजना में भी राज्य अव्वल

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी के क्रियान्वयन की तैयारियों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। श्रमिकों की 98 प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कर राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि परिसंपत्तियों की 99 प्रतिशत जियो टैगिंग के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में भी राज्य अव्वल रहा है।

'मोर गांव-मोर पानी' अभियान को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न विकासखंडों में जल उपलब्धता के आधार पर जल संरक्षण कार्यों पर न्यूनतम निर्धारित व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के 'मोर गांव-मोर पानी' महाअभियान को भी इस योजना से नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 में वीबी-जी राम जी के लिए 5,591.42 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रखा गया है। वहीं अप्रैल से जून 2026 की पहली तिमाही में ही 1,264 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है।

आत्मनिर्भर नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़ : महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय

किसी भी राज्य के विकास की वास्तविक पहचान वहां की महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता से होती है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार सशक्त होता है, समाज प्रगतिशील बनता है और विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सुशासन का प्रमुख आधार बनाया है। वर्ष 2026 को 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में मनाते हुए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित योजनाएं आज लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल महतारी वंदन योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का सशक्त माध्यम बन चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 66 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। अब तक 29 किस्तों के माध्यम से 18 हजार 805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ कर रही है। इस योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में आंगनबाड़ी संचालन हेतु 800 करोड़ रुपये, पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपये तथा कुपोषण मुक्ति एवं पोषण योजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी सदन स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 368 महतारी सदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 137 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2026–27 में 250 नए महतारी सदनों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, आजीविका और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में 34 सखी वन–स्टॉप सेंटर संचालित किए हैं। यहां घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और संकटग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सकीय सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 के समन्वय से त्वरित सहायता व्यवस्था भी प्रभावी रूप से संचालित हो रही

है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जिसने सखी वन-स्टॉप सेंटरों के संचालन के लिए डिजिटल एसओपी लागू की है।

महिलाओं की आर्थिक प्रगति को नई गति देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन और विपणन से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार 200 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण कर रही है, जहां महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिवर्ष युवा रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा तथा लखपति दीदी भ्रमण योजना के माध्यम से सफल उद्यमियों को देश-विदेश के अध्ययन भ्रमण का अवसर मिलेगा।

बिहान मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 2.92 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनसे 31.65 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री के तीन करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए अब तक 10 लाख 43 हजार से अधिक लखपति दीदी तैयार की हैं। रेडी-टू-ईट निर्माण, कृषि आधारित उद्यम, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण तथा हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों ने ग्रामीण महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

महिला निर्माण श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र बेटियों को 20 हजार रुपये, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 7,900 रुपये, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत अनुदान तथा मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला श्रमिकों को 20 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 24 हजार से अधिक बालिकाओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है। प्रत्येक जोड़े के विवाह के लिए राज्य सरकार 50 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करा रही है। वहीं महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 42,878 महिला समूहों को 129.46 करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया गया है। महतारी शक्ति ऋण योजना के माध्यम से महिलाओं को बिना जमानत 25 हजार रुपये तक का ऋण स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 38 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। सुशिक्षा योजना के तहत 2 लाख 18 हजार 139 छात्राओं को प्रतिमाह 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। शुचिता योजना के माध्यम से 2 हजार विद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं तथा लाखों किशोरियों को मासिक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

महिला समूहों के उत्पाद आज वैश्विक पहचान भी बना रहे हैं। आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित जशप्योर ब्रांड 'वोकल फॉर लोकल' अभियान का सफल उदाहरण बन चुका है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। वहीं सखी साड़ी-मिलेट कैफे जैसी पहलें स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

आज छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का व्यापक अभियान बन चुका है। आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण पोषण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास, स्वरोजगार और सम्मानजनक जीवन की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयास महिलाओं के जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में प्रदेश की महिलाएं आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। यही बदलती तस्वीर छत्तीसगढ़ को 'सुशासन से समृद्धि' की ओर निरंतर अग्रसर कर रही है।

– डॉ. दानेश्वरी संभाकर,
उप संचालक, जनसंपर्क विभाग, छग

न हिंदू न मुसलमान बल्कि बचपन और जवानी खतरे में ...

स्वतंत्र बोल- डेस्क

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देश में हिंदू, मुसलमान, क्षत्रिय, ब्राह्मण समेत अन्य कोई भी जाति खतरे में नहीं है। भारतीय बचपन खतरे में हैं। देश की जवानी, देश का वर्तमान और भविष्य खतरे में है। कुछ लोग आंदोलन के लिए देश के बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था आदि को लेकर आंदोलन होना चाहिए। व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

वे सोमवार को राजधानी के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केवल एक पीएम देश को ठीक कर देंगे, यह भी अपेक्षा पूरी तरीके से उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति से बहुत कुछ देश में अच्छा हुआ है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं दिखता, यह गलत है। हमेशा न्यायपूर्ण दृष्टि से सोचना चाहिए।

धैर्य रखें साकार होगा अखंड भारत

उन्होंने छत्तीसगढ़ में मतांतरण रोधी कानून और धार्मिक उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि यह सब राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। देश में हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म को कोई खतरा नहीं है। असली खतरा भारत की प्रतिष्ठा, मान और मर्यादा को है। अतीत में जो भी धार्मिक मतांतरण हुए उसे लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में किसी का उत्पीड़न न हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक दिन फिर से भारत का हिस्सा बनेंगे। लोगों को इसके लिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है।

सनातन धर्म में कोई कमी नहीं

रामदेव ने कहा कि सनातन संस्कृति और धर्म अनादि हैं। इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है कि लोगों को दूसरा धर्म अपनाना पड़े। कुछ लोगों ने तलवार, लालच और भ्रांतियों के बल पर सनातन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, जिस पर हम शांत रहे। सनातन धर्म में जातिवाद या छुआछूत की कोई जगह नहीं है। यह केवल कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों की देन है। भगवान राम की मर्यादा, श्रीकृष्ण के योग-कर्म और भगवान शिव की पवित्रता को अपनाकर ही मतांतरण जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है।

'बौद्धिक अराजकता' पर साधा निशाना

रामदेव ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में 'बौद्धिक अराजकता' फैलाना पूरी तरह से गैर-लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन यह स्वतंत्रता संवैधानिक, नैतिक और आध्यात्मिक सीमाओं के भीतर ही होनी चाहिए और इसका उपयोग देश के विनाश के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

देश को आगे ले जाने युवाओं को सामने आना होगा..

भारत के 80वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर केशव कुंज में श्री केशव स्मारक समिति के तत्वाधान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल जी ने ध्वजारोहण किया। समारोह के प्रारंभ में राष्ट्र गीत वन्दे मातरम तथा ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के दल ने ध्वज को सलामी दी।देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि भारत अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अपना देश सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ। अपनी स्वतंत्रता के पीछे लगभग एक हजार वर्षों का संघर्ष है। इसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। आज सबसे पहले उन महापुरुषों एवं महिलाओं को स्मरण करें, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी अथवा जीवन भर कारागारों के पीछे रहे। सिंध के राजा दाहिर, दिल्ली के राजा अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, दक्षिण भारत की चेन्नमा, विजय नगर साम्राज्य के लोग जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए बलिदान हुए। देश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता के लिए यह संघर्ष चला। अंग्रेजों के समय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और लंबे समय तक संघर्ष करते रहने वाले देश के प्रत्येक प्रांत के बंधुगण, माताएं एवं बहनें, हम उन सभी का स्मरण करते हैं, जिनके बलिदानों के कारण यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। डॉ. कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश ने प्रगति की। हमारा देश तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ कि सारा देश एकजुट होकर आगे बढ़े और विश्व के सामने एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत करे।

युवा शक्ति ही देश की असली ताकत - भागवत

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कस्तूरचंद पार्क मैदान में नागपुर महानगरपालिका के सहयोग से समाचार समूह द्वारा स्थापित 200 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया। विशेष कार्यक्रम में 'भारत के उज्ज्वल भविष्य में युवाओं का योगदान' विषय पर मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर 'लोकमत' एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन तथा पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. विजय दर्डा और महापौर नीता ठाकरे उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम में सरसंघचालक जी ने कहा कि भारत के पास मौजूद विशाल युवा आबादी केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस 'डेमोक्रेटिक डिविडेंड' का सही उपयोग किया जाए तो भारत विश्वगुरु बन सकता है। इसके लिए युवा शक्ति को उचित दिशा, कौशल और अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। युवाओं को केवल अपने भविष्य के बारे में न सोचते हुए देश और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे समय में देश के सामने सबसे बड़ा अवसर उसकी युवा आबादी है। अनेक पीढ़ियों ने देश के लिए त्याग किया, जिसके कारण आज की पीढ़ी स्वतंत्रता का आनंद ले रही है। अब आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की है। युवाओं में ऊर्जा, सपने और कुछ अलग करने की ललक होती है। दुनिया के संघर्षों का पर्याप्त अनुभव नहीं होने के कारण उनमें आशावाद भी अधिक होता है। इस ऊर्जा को सही दिशा देना और राष्ट्र निर्माण में उसका उपयोग करना आवश्यक है। युवाओं को अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हुए बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाना चाहिए।

मोहन भागवत जी ने कहा कि युवा आबादी भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। हालांकि यह अवसर अपने आप विकास में परिवर्तित नहीं होगा। शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, रोजगार सृजन और राष्ट्रहित की भावना के

माध्यम से ही 'डेमोक्रेटिक डिविडेंड' को राष्ट्रीय शक्ति में बदला जा सकता है। रोजगार का अर्थ केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। उद्योग और व्यवसाय में जोखिम होते हैं और युवाओं में इन जोखिमों का सामना करने का साहस होना चाहिए। स्वयं रोजगार प्राप्त करने के साथ ही दूसरों के लिए रोजगार पैदा करने की मानसिकता भी विकसित होनी चाहिए। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में युवाओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

भारत को दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए

भारत को अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी संस्कृति, मूल्यों और आवश्यकताओं के आधार पर विकास की दिशा तय करनी चाहिए। दुनिया आज अधूरी दृष्टि के कारण संघर्ष कर रही है। ऐसे में दुनिया को आगे का मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी भारत की है। इसके लिए युवा पीढ़ी को साहस, कर्मशीलता, त्याग और शौर्य के बल पर स्वयं को तैयार करना होगा। देश की प्रतिष्ठा और सुरक्षा को मजबूत करने में युवाओं को आगे आना चाहिए।

लोकतंत्र में अलग-अलग विचार और विरोधी दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। सवाल मजबूती से उठाना, आंदोलन करना और विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन ऐसा करते समय संविधान और उसकी मर्यादाओं का ध्यान रखना जरूरी है।

गोधन संरक्षण को नई पहचान

गायों के संवर्धन के लिए शुरू हुआ 'सुरभि गौधाम'

स्वतंत्र बोल- डेस्क

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला बिलासपुर के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम लाखासार स्थित गौधाम का शुभारंभ करते हुए प्रदेश में गोधन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने गोमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करने के उपरांत गौधाम परिसर का अवलोकन कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने गौधाम में आश्रय प्राप्त बेसहारा एवं आवारा पशुओं की देखरेख, चारा, पानी तथा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और चारागाह का भी अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि ग्राम लाखासार में लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में गौधाम विकसित किया गया है, जिसमें से 19 एकड़ भूमि पर पशुओं के लिए हरे चारे की खेती की जा रही है। गौधाम का संचालन कामधेनु गौशाला समिति द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही गौधाम योजना का उद्देश्य प्रदेश में बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि गोधन हमारी ग्रामीण संस्कृति, कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गोधन संरक्षण और बेसहारा मवेशियों की देखभाल के लिए गौधाम योजना को राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है, जिससे गौसेवा की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ ही पशुधन संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि अब राज्य के सभी गौधाम 'सुरभि गौधाम' के नाम से जाने जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के गौधामों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। गौधामों में पशुपालन, हरा चारा उत्पादन तथा गोबर से उपयोगी वस्तुएं तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे गौसेवा के साथ-साथ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लाखासार ग्राम के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने लाखासार में महतारी सदन, मिनी स्टेडियम तथा 500 मीटर लंबाई के गौरव पथ के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही लाखासार गौधाम में प्रशिक्षण भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत करने तथा एक काऊ कैचर और एक पशु एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में गौसंरक्षण और स्थानीय विकास कार्यों को और मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्र के पशुपालकों और ग्रामीणों से संवाद कर गोधन संरक्षण के

लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली तथा इस सेवा कार्य में लगे लोगों की सराहना की। उन्होंने गौसेवा से जुड़े कार्यकर्ताओं को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार सेवा कार्य जारी रखने की बात कही और सभी को गोधन संरक्षण तथा गौसेवा के लिए प्रेरित किया।

तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुँमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी वादा करते हैं, उसे अवश्य पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा तखतपुर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा अनेक कार्य प्रगतिरत हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से क्षेत्र में विकास को नई गति मिली है।

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल ने स्वागत उद्बोधन देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का अभिनंदन किया और गौधाम योजना के शुभारंभ के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से गोधन संरक्षण को नई दिशा मिलेगी तथा बेसहारा और निराश्रित गौवंश के संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम, विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, कमिश्नर बिलासपुर सुनील जैन, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, संचालक पशु चिकित्सा चंद्रकांत वर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

विकसित भारत के संकल्प में विकसित छत्तीसगढ़ की होगी महत्वपूर्ण भूमिकाः मुख्यमंत्री साय

स्वतंत्र बोल- डेस्क

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस माँ भारती की वंदना, हमारे गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का पावन अवसर है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. भीमराव अंबेडकर और वीर सावरकर सहित स्वतंत्रता संग्राम के असंख्य सेनानियों के त्याग और बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वतंत्रता और स्वाभिमान की अलख जगाने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह, धुरवा राव, यादव राव, वेंकट राव, डेबरी धुर और आयतु माहरा सहित जननायकों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का संदेश – 'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं', संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास जी का 'मनखे-मनखे एक समान' का उद्घोष हमें स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा के मूल्यों की निरंतर प्रेरणा देता है। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का उल्लेख करते हुए उनके राष्ट्रीय एकता के संकल्प का स्मरण किया।

बस्तर में शांति के साथ विकास का नया सूर्योदय

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक

सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन बदलते बस्तर की नई पहचान का प्रतीक है। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'नियद नेल्ला नार 2.0' और 'बस्तर मुन्ने अभियान' के माध्यम से 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करते हुए बस्तर संभाग के 39 लाख से

अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। नक्सल हिंसा के कारण बंद पड़े स्कूलों को पुन: प्रारंभ करने के साथ 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है।

'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' में 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर हेल्थ प्रोफाइल तैयार की गई है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की 'आजीविका उन्नयन योजना' तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं तथा वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू 'सेवा डेरा' के माध्यम से नागरिक सुविधाओं, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में सड़क, बिजली, परिवहन और संचार की मजबूत बुनियाद तैयार की जा रही है। सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत 461 गांवों को ग्रिड आधारित बिजली प्रणाली से जोड़ने तथा 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा' से बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल रही है।

अन्नदाता की समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता हैं और उनका सुख, सम्मान तथा समृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जा रहा है। 'कृषक उन्नति योजना' की राशि का एकमुश्त भुगतान होली से पहले किया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रही है। धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसल लेने पर 'कृषक उन्नति योजना' के अंतर्गत 15 हजार रुपए की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना के अनुरूप प्रदेश के 2,028 पैक्स का

कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया है और इनमें से 1,988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं।

सिंचाई विस्तार के लिए 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को जोड़ने की सोच को आगे बढ़ाते हुए 'सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना' के लिए 3,047 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है।

अटल सिंचाई योजना के माध्यम से बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इंद्रावती नदी पर लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाएंगे, जिनसे 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें साढ़े पांच हजार रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया जा रहा है तथा 'चरण पादुका योजना' पुन: प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'मोदी की गारंटी' के अनुरूप प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति के बाद अब तक 24 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में

दिमागी नक्सल: विरोध की राजनीति का नया नाम...

स्वतंत्र बोल- डेस्क

15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि भारत ने हथियारबंद नक्सलवाद पर काफी हद तक विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलों से सावधान रहने की जरूरत है. प्रधानमंत्री का संकेत उन विचारों और प्रवृत्तियों की ओर था जो समाज में निराशा, अराजकता और विकास-विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देती हैं. लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सर्वोपरि है.

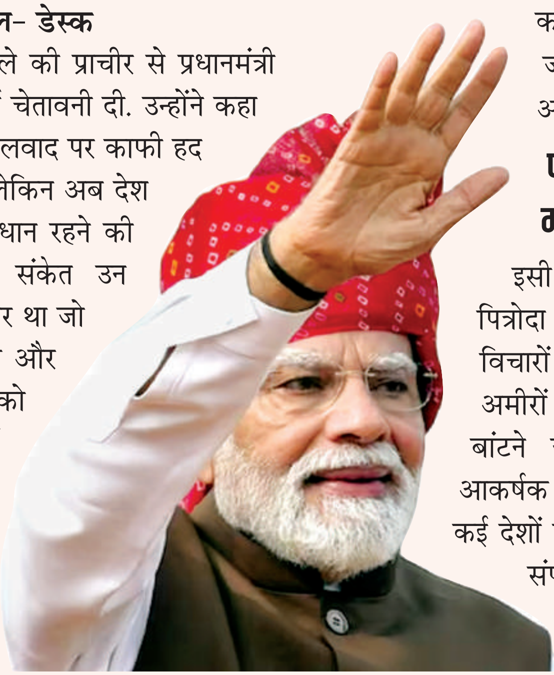

सरकार की आलोचना करना, नीतियों पर सवाल उठाना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है. लेकिन असहमति और विकास-विरोधी विमर्श के बीच एक स्पष्ट रेखा भी होती है. समस्या तब पैदा होती है जब तथ्य और तर्क की जगह वैचारिक पूर्वाग्रह ले लेते हैं और हर विकास परियोजना को शोषण, हर आर्थिक सुधार को साजिश तथा हर राष्ट्रीय उपलब्धि को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगता है.

पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं. बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का यह बयान कि राज्य में बन रहे हाईवे और सड़कें बिहार का पानी लूटने के लिए बनाई जा रही हैं, को इसी श्रेणी में देखा जा सकता है. सड़कें किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति की रीढ़ होती हैं. वे उद्योग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाती हैं. यदि विकास की ऐसी बुनियादी परियोजनाओं को भी जनता के शोषण का माध्यम बताकर प्रस्तुत किया जाए, तो इससे समाज में भ्रम और अविश्वास ही पैदा होता है.

पीएम ने गायों को चारा और मोरों को खिलाया दाना

इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के संपत्ति पुनर्वितरण संबंधी विचारों पर भी व्यापक बहस हुई. अमीरों की संपत्ति को बड़े पैमाने पर बांटने जैसे विचार पहली नजर में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों का अनुभव बताता है कि केवल संपत्ति के पुनर्वितरण से समृद्धि नहीं आती. समृद्धि का निर्माण उद्यम, निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन से होता है. यदि समाज में यह संदेश जाए कि सफलता दंड का कारण बन सकती है, तो निवेश और उद्यमशीलता दोनों प्रभावित होते हैं.

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. देश में रिकॉर्ड स्तर पर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का विस्तार हो रहा है. सरकार की नीतियों से असहमति हो सकती है, लेकिन हर विकास परियोजना को संदेह की दृष्टि से देखना और जनता के मन में यह धारणा बनाना कि विकास वास्तव में शोषण का दूसरा नाम है, राष्ट्रहित में नहीं कहा जा सकता। इतिहास भी हमें यही सिखाता है. नक्सलवाद की शुरुआत केवल बंदूक से नहीं हुई थी. उसके पीछे एक वैचारिक ढांचा था जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को अस्वीकार करता था और व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष तथा टकराव को ही एकमात्र रास्ता मानता था।

बांग्लादेश को 'इस्लामिक NATO' में लाने की तैयारी

बांग्लादेश को पाकिस्तान और तुर्की के करीब लाने की अटकलों को अब तुर्की के अखबार येनी शफाक ने हवा दी है. अखबार ने एक विश्लेषण में यह कल्पना की है कि अगर बांग्लादेश सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के उभरते रक्षा ढांचे का हिस्सा बनता है तो इसका दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा. हालांकि, रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बांग्लादेश को इस फ्रेमवर्क में शामिल करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।

येनी शफाक के मुताबिक, अगर ढाका इस तरह के किसी रक्षा ढांचे से जुड़ता है तो यह उसकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा. अखबार का मानना है कि बांग्लादेश भारत पर अपनी पारंपरिक निर्भरता कम करते हुए चीन, भारत और पश्चिम के साथ रिश्तों के अलावा एक नया सुरक्षा विकल्प तलाश सकता है. रिपोर्ट में इसे किसी एक देश के खिलाफ सीधा कदम नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है.

पाकिस्तान-तुर्की से बढ़ेगा रक्षा सहयोग

अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान और तुर्की बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं. खास तौर पर तुर्की की ड्रोन और रक्षा तकनीक बांग्लादेश के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है. बांग्लादेश और तुर्की के बीच पहले से रक्षा सहयोग बढ़ रहा है और दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में संस्थागत बातचीत आगे बढ़ाने के लिए कदम भी उठाए हैं.

भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है मुश्किल?

येनी शफाक के विश्लेषण में भारत को लेकर खास तौर पर कहा गया है कि बांग्लादेश अगर इस रक्षा ढांचे के करीब जाता है तो नई दिल्ली को अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ रिश्तों को नए तरीके से देखना पड़ सकता है. भारत-बांग्लादेश की करीब 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा, व्यापार, नदी जल बंटवारे और बंगाल की खाड़ी से जुड़े मुद्दों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

अखबार का दावा है कि तुर्की की रक्षा तकनीक और पाकिस्तान का सैन्य अनुभव बांग्लादेश की सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है. इससे भारत के लिए अपने पूर्वी समुद्री इलाके में रणनीतिक समीकरणों पर नजर रखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा.

अभी सिर्फ अटकलें, कोई आधिकारिक फैसला नहीं

पूरी रिपोर्ट की सबसे अहम बात यही है कि बांग्लादेश के इस रक्षा ढांचे में शामिल होने की बात अभी सिर्फ एक संभावित परिदृश्य है. कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन बांग्लादेश और तुर्की के बीच हाल के महीनों में रक्षा और रणनीतिक सहयोग जरूर बढ़ा है. जून में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए मंत्री स्तर की संयुक्त समिति बनाने पर सहमति जताई थी.

ऐसे में येनी शफाक का यह विश्लेषण भले ही अटकलों पर आधारित हो, लेकिन यह दिखाता है कि तुर्की के रणनीतिक हलकों में बांग्लादेश को पाकिस्तान-तुर्की-सऊदी सुरक्षा ढांचे के संभावित हिस्से के तौर पर देखना शुरू किया गया है. दूसरी तरफ, इस रक्षा फ्रेमवर्क का विस्तार असल में होता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी।

छात्रों के जिद के आगे झुका सोरेन सरकार

स्वतंत्र बोल- डेस्क

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर चला 24 दिन का छात्र आंदोलन सोमवार को उस समय बड़े मोड़ पर पहुंचा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया. इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्र नेताओं देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. हालांकि सीबीआई जांच की मांग अब भी अधूरी है, इसलिए आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा।

आंदोलन की शुरुआत जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुई थी. हजारों अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटकर धरने पर बैठ गए और जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा तथा जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगाए. इस पूरे आंदोलन की खास बात यह रही कि इसे किसी एक राजनीतिक दल का मंच नहीं बनने दिया गया. स्टेडियम में दो अलग मंच बनाए गए थे ताकि आंदोलन गैर-राजनीतिक बना रहे।

अगस्त की शुरुआत में आंदोलन ने भूख हड़ताल के साथ नया मोड़ लिया. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया. उनके साथ उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति समेत कुल आठ प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठे. महतो ने चौथे दिन ही कहा था कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, यह लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कफन में लिपटना पड़े. भारी बारिश के बीच राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद पहुंचे और डॉक्टरों को इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

9 अगस्त को सरकार और छात्रों के बीच मैराथन बातचीत हुई. सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और 2023-2025 की बैकलॉग परीक्षाएं रद्द कीं और तीनों जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसे 98 प्रतिशत मांगें मानने का दावा बताया, लेकिन जेएसएससी-सीजीएल रद्द करने और

सीबीआई जांच की मांग उस वक्त ठुकरा दी गई थी.

इस आंशिक फैसले से नाराज छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च निकाला. पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया. इस दौरान देवेंद्र महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई, ब्लड शुगर तेजी से गिरा और उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा. उनके सहयोगी ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज में उन्हें चोट भी आई. इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और कई छात्र घायल हुए। इस घटना ने राजनीतिक पारा भी चढ़ा दिया. अगले दिन यानी 11 अगस्त को बीजेपी ने राज्यव्यापी बंद बुलाया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उसी दिन एबीवीपी ने भी पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक मार्च निकाला, जिसमें कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और सिर्फ बातचीत से समाधान निकल सकता है. इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद झारखंड में जेएमएम के साथ सरकार में है, इसलिए राहुल गांधी का बयान दोहरा मापदंड है. दिल्ली में जंतर-मंतर पर चले कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन से भी झारखंड आंदोलन की तुलना होती रही, और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी झारखंड के मामले में मूकदर्शक बनी रही जबकि यह आंदोलन उन्हीं के धुर विरोधियों के राज्य में चल रहा था।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस- निवेशकर्ताओ के लिए छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पहल

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) का मतलब व्यापर के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना ताकि निवेशकर्ताओं को आसानी से कागजी प्रक्रियाओं को पूर्ण उद्योग व्यापार लगा सके। आम टूर पर देखा जाता है कि नए उद्योग या बड़ा काम शुरू होने के पहले सैकड़ो सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते काम प्रभावित होता है और निवेशक निराश होते है। किसी भी उद्योगिक घराने को काम करने के लिए बेहतर माहौल की जरुरत होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने निवेशकों के लिए दरवाजा खोल दिया है, उन्हें बेहतर माहौल देने अनेक तरह की योजनाए बनाई गई।

विष्णु देव साय ने उद्योग और कारोबार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए मानसून सत्र में 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026' पारित कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित (रिस्क बेस्ड) एवं विश्वास आधारित (ट्रस्ट बेस्ड) बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा। इस विधेयक का उद्देश्य उद्योगों एवं कारोबार की स्थापना और

संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालनों को कम करना तथा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अधिक पारदर्शी, तेज और उद्यम-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है।

इन्हे मिलेगा फायदा-

राज्य सरकार ने निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी और जटिलताओं से राहत मिलेगी। विधेयक में डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण , तृतीय-पक्ष सत्यापन , जोखिम-आधारित निरीक्षण तथा दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया गया है। छोटे कारोबारियों को बड़े उद्योगों जैसी जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत कम जोखिम वाले उद्यमों में बार-बार होने वाले विभागीय निरीक्षणों के स्थान पर सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा लाइसेंसधारी अभियंता, आर्किटेक्ट या अन्य अधिकृत पेशेवरों द्वारा प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे अनुमतियों की प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक जवाबदेह बनेगी।इन सुधारों से निवेशकों के लिए कारोबारी माहौल अधिक अनुकूल बनेगा, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

विधेयक के तहत हर वर्ष लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू की जाएगी। इससे उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार के विस्तार एवं संचालन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। एमएसएमई इकाइयों के लिए जल प्रदाय संबंधी अनुमति स्व-घोषणा के आधार पर, सोसायटी अथवा फर्म का पंजीयन समयबद्ध प्रक्रिया से तथा भवन अनुज्ञा सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की जा सकेगी। निर्धारित समय-सीमा में संबंधित विभाग द्वारा निर्णय नहीं लेने की स्थिति में पात्र मामलों में अनुमति स्वत: स्वीकृत (ऑटो अप्रूवल) मानी जाएगी। हालांकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में तकनीकी परीक्षण एवं भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

8 विभागों के 43 सेवाओं को शामिल किया-

राज्य सरकार ने शासन के 8 विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली 43 सेवाओं को जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली के दायरे में शामिल किया गया है।आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका परिषद की मंजूरी से अतिरिक्त सेवाएं भी इसमें जोड़ी जा सकेंगी। इस सुधार से राज्य के 15 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि भरोसे, स्व-घोषणा और समयबद्ध सेवाओं पर आधारित यह व्यवस्था कारोबार शुरू करने और संचालित करने में लगने वाले समय एवं लागत को कम करेगी, जबकि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और परीक्षण की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।

विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति इसके क्रियान्वयन और अनुश्रवण की जिम्मेदारी निभाएगी। दोनों समितियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी। 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026' राज्य में पारदर्शी, सरल, पूर्वानुमेय और निवेश-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

धुरंधर के बाद अब 'प्रलय' की तैयारी

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी नई ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'धुरंधर' (2025) और 'धुरंधर - द रिवेंज' (2026) के बाद एक बार फिर पर्दे पर धमाका करने की तैयारी में हैं. दुनिया के अंत की कहानी पर आधारित उनकी नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर मुंबई में शुरू हो चुकी है. इस बड़े प्रोजेक्ट में रणवीर सिंह न सिर्फ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी है.

इस बड़े बजट की फिल्म का निर्माण अनन्या बिड़ला के 'बिड़ला स्टूडियोज', हंसल मेहता और साहिल सहगल की 'ट्रू स्टोरी फिल्म्स' और रणवीर सिंह की अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'मां कसम फिल्म्स' मिलकर कर रहे हैं. प्रोडक्शन से जुड़े दिग्गजों का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है।

डायरेक्टर और मुख्य स्टारकास्ट

फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं. जय इससे पहले मशहूर सोनीलिव सीरीज 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' (2020) के सह-निर्देशक और जियोहॉटस्टार की सीरीज 'लुटेरे' (2024) के डायरेक्टर के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ कल्याणी प्रियदर्शन भी लीड रोल में दिखाई देंगी, जिन्हें 2025 में आई फिल्म 'लोकाह चैप्टर वन: चंद्र' से काफी सराहना मिली थी.

क्या होगी प्रलय की कहानी?

'प्रलय' की कहानी एक ओरिजिनल कांसेप्ट पर आधारित है, जो दुनिया में आने वाले विनाश और उसके बीच इंसान के जिंदा बचने के संघर्ष (सर्वाइवल) को दिखाती है. कहानी का मुख्य केंद्र मुंबई है, इसलिए फिल्म की पूरी शूटिंग भी मुंबई और उसके आसपास की असली लोकेशन्स पर ही की जा रही है. मेकर्स का मानना है कि असली जगहों पर शूटिंग करने से कहानी में असलियत, गहराई और भव्यता का एक अनोखा एक्सपीरियंस मिलेगा. इस विजन को पूरा करने के लिए भारत के साथ-साथ विदेशी तकनीशियनों और कलाकारों की टीम भी काम कर रही है.

तैयारियां और मेकर्स का भरोसा

फिल्म को पर्दे पर उतारने से पहले कई महीनों तक बेहद मुश्किल और तकनीकी प्री-प्रोडक्शन प्रक्रिया पर काम किया गया, जिसके बाद अब शूटिंग शुरू हुई है. फिल्म को लेकर निर्माता हंसल मेहता काफी एक्साइटेड हैं. वैरायटी को दिए एक बयान में उन्होंने कहा था कि 'प्रलय' एक ऐसी फिल्म है जिसे भारत में आज तक कभी नहीं बनाया गया है और न ही दर्शकों ने ऐसा अनुभव पहले कभी पर्दे पर देखा है.

धुरंधर थी आखिरी फिल्म

रणवीर सिंह को आखिरी बार 'धुरंधर द रिवेंज' में देखा गया था, जिसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर ने हमजा अली मज़ारी और जसकीरत सिंह रंगी का रोल निभाया था।

नफरत नहीं, इंसानियत सिखाती है बंटवारा

कुछ दर्द ऐसे होते हैं, जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है. उस दर्द को वही लोग समझ सकते हैं, जो उससे गुजरे हैं. 14 अगस्त 1947 के दिन लाखों-करोड़ों लोगों ने एक ऐसा दर्द झेला, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता. भारत-पाकिस्तान, ये दो देश धर्म के नाम पर बनकर अलग हो गए. बंटवारे में दोनों देशों के अंदर क्या-क्या हुआ, ये तो हर कोई जानता है. मगर इसी बीच एक ऐसी कहानी का भी जन्म हुआ जिसने धर्म, जाति, भेदभाव- इन सभी चीजों को इंसानियत के दम पर अलग कर दिया।

मशहूर राइटर असगर वजाहत ने बंटवारे के हादसों पर आधारित एक नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' का निर्माण किया था, जिसका मतलब है कि जिसने लाहौर नहीं देखा, वो जन्मा ही नहीं. इसी नाटक पर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और आमिर खान अपनी फिल्म 'बंटवारा 1947' लाए हैं, जिसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी जैसे मेगा स्टार्स शामिल हैं. आज बंटवारे के ही दिन रिलीज हुई ये फिल्म हमें कैसी लगी? आइए, आपको विस्तार से बताते हैं.

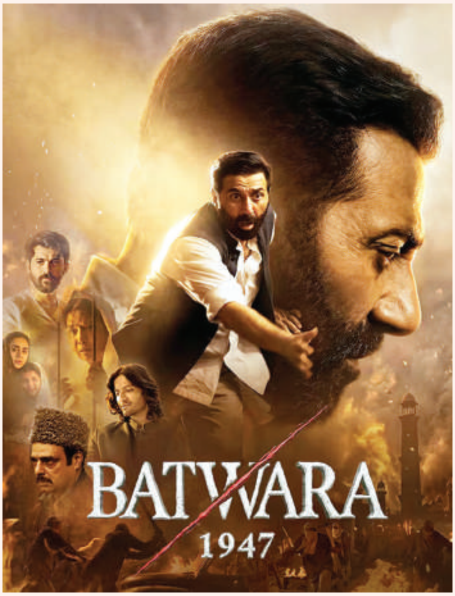

क्या है बंटवारा 1947 की कहानी?

मेरठ के एक प्रिंटिंग खारखाने के मालिक सिकंदर मिर्जा (सनी देओल) अपने परिवार के साथ भारत की आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं. शहर में उनकी हर कोई बड़ी इज्जत करता है. मगर आसपास हो रहे हिंदू-मुसलमान दंगों के कारण उन्हें अपना देश छोड़कर पाकिस्तान के लाहौर जाना पड़ता है. अपनी पत्नी हामिदा (प्रीति जिंटा), बेटे जावेद (करण देओल) और बेटी तन्नू (खुशी हजारे) के साथ वो लाहौर जाने वाली ट्रेन में बैठ चुके होते हैं, लेकिन किसी कारण से उसका बेटा जावेद नहीं आ पाता. मिर्जा अपने परिवार के साथ अब लाहौर आ चुका है, जहां उसे हबीब अख्तर काजमी (अली फजल) एक घर दिलाने में मदद करता है.

मगर उस घर में पहले से ही एक बूढ़ी औरत दुर्गावति किशनपाल देवी यानी माई (शबाना आजमी) रह रही होती हैं. वो घर उनके बेटे रतन का है, जो बंटवारे की आग में अपने पूरे परिवार सहित झुलस चुका है. मिर्जा और उसका परिवार एक हिंदू बुढ़िया को अपने घर में पनाह देने के लिए याकूब खान (अभिमन्यु सिंह) के निशाने पर हैं. इस वजह से लाहौर की गलियों में फिर से उग्रवाद बढ़ने लगता है. याकूब किसी भी कीमत पर माई को घर से बाहर निकालना चाहता है. इस कोशिश में वो मिर्जा के परिवार पर भी हमला करता है. ऐसे में सिकंदर मिर्जा इस धर्म के कारण फैली नफरत से कैसे अपने परिवार और बूढ़ी माई को बचाएगा? यही पिक्चर का बेसिक प्लॉट है.

रोंगटे खड़े करती है बंटवारे की ये कहानी

पिक्चर की कहानी वैसे काल्पनिक है, यानी इसका असल जिंदगी से कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन इस काल्पनिक कहानी ने वही बंटवारे का दर्द दोबारा जिंदा किया, जिसमें कोई नफरत या ओवर द टॉप ड्रामा नहीं डाला गया. बल्कि एक साधारण सी कहानी बताई गई, जो इंसानियत और मां के इमोशन्स पर रखी गई। बंटवारा 1947 फिल्म अपने हर किरदार के साथ छिपे इमोशन को बड़ी खूबसूरती से पेश करती है. सनी देओल-प्रीति जिंटा के किरदारों के साथ विभाजन के दौरान जो कुछ हुआ, वो इमोशन आप फील भी करते हैं।

भारत ने पहली बार जीता कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का खिताब

भारत ने 13 स्वर्ण समेत 35 पदक जीती

भारतीय तलवारबाजी दल ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने चार दिन तक चली प्रतियोगिता में अंडर-23 और सीनियर वर्ग को मिलाकर कुल 35 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल रहे। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने प्रतिष्ठित विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया। यह ट्रॉफी 1982 से कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की ओर से उस देश को दी जाती है, जो प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ ओवरऑल प्रदर्शन करता है।

सीनियर टीम स्पर्धाओं में भारत का दबदबा

भारतीय फेंसर्स ने सीनियर टीम स्पर्धाओं में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए छह में से पांच स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारत ने पुरुष साबरे, महिला साबरे, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में कड़े मुकाबले के बाद रजत पदक हासिल किया। टीम स्पर्धाओं में इस दबदबे के साथ भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान पक्का किया और पहली बार कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का ओवरऑल खिताब अपने नाम किया।

पहले दिन ही 17 पदकों की बंपर शुरुआत

भारत के लिए अभियान की शुरुआत ही शानदार रही। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर-23 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 17 पदक जीते, जिसमें चार स्वर्ण, चार रजत और नौ कांस्य पदक शामिल थे। पुरुष साबरे में भारत ने पोडियम पर क्लीन स्वीप किया। निखिल वाघ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा जॉयस अशिता ने महिला फॉयल, प्राची लोहान ने महिला एपी और जेफरलिन ने महिला साबरे में स्वर्ण पदक जीता।

दूसरे दिन सीनियर खिलाड़ियों ने दिखाया दम

दूसरे दिन भारतीय दल ने सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सात पदक हासिल किए। इसमें एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक शामिल रहे। महिला सीनियर एपी में तनिष्का खत्री और खुशी दाभाड़े ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीतकर भारत का दबदबा कायम रखा।

तीसरे दिन तीन स्वर्ण समेत पांच पदक

प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी भारतीय फेंसर्स का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारत ने तीन स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य सहित कुल पांच पदक जीते। सीनियर महिला फॉयल में कनागलक्ष्मी, सीनियर पुरुष एपी में राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन और सीनियर पुरुष साबरे में सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

सपोर्ट स्टाफ की भी अहम भूमिका

भारत की ऐतिहासिक सफलता में खिलाड़ियों के साथ कोच और सपोर्ट स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोच भारतजी ठाकोर, श्रीहरि पिसे और शंकर नारायणन ने खिलाड़ियों को रणनीतिक मार्गदर्शन दिया। फिजियोथेरेपिस्ट अमृता बालकवाड़े ने खिलाड़ियों की फिटनेस का ध्यान रखा, जबकि टीम मैनेजर मनु त्यागी ने पूरे अभियान के दौरान टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली।

इगा स्वियातेक ने जीता कनाडियन ओपन का खिताब

पोलैंड की छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा स्वियातेक ने 2026 सत्र का अपना पहला खिताब जीत लिया है। उन्होंने गुरुवार को खेले गए कनाडियन ओपन के फाइनल में दुनिया की नंबर-2 खिलाड़ी और मौजूदा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन एलेना रिबाकिना को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया। ओलंपिक्स डॉट कॉम के अनुसार, स्वियातेक ने यह मुकाबला महज 75 मिनट में अपने नाम किया।

पहले सेट से ही स्वियातेक का दबदबा

स्वियातेक ने मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। उन्होंने पहले सेट में मिले दोनों ब्रेक प्वाइंट मौकों को भुनाया, जबकि रिबाकिना को मिले दोनों ब्रेक प्वाइंट बचा लिए। इसके साथ ही उन्होंने पहला सेट 6-2 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में भी पोलिश खिलाड़ी ने अपना दबदबा कायम रखा। उन्होंने एक भी ब्रेक प्वाइंट का सामना नहीं किया और मिले तीन मौकों में से दो को जीत में बदलते हुए सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया।

जीत के बाद कही ये बात

खिताब जीतने के बाद स्वियातेक ने कहा, 'मैं यह खिताब उन सभी लोगों को समर्पित करना चाहती हूं, जो अनुचित फैसलों और नफरत का सामना कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि खुद पर ध्यान केंद्रित रखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि भविष्य में क्या हासिल किया जा सकता है।

रिबाकिना के खिलाफ बढ़त

इस जीत के साथ स्वियातेक ने रिबाकिना के खिलाफ अपने डब्ल्यूटीए टूर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड को 7-6 कर लिया। उन्होंने रिबाकिना के खिलाफ लगातार दो हार के सिलसिले को भी खत्म किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह दूसरी फाइनल भिड़ंत थी और दोनों ही मौकों पर स्वियातेक ने सीधे सेटों में जीत दर्ज की है।

12वां डब्ल्यूटीए 1000 खिताब

टोरंटो में मिली जीत स्वियातेक का 12वां डब्ल्यूटीए

1000 खिताब है। इसके साथ ही उन्होंने आर्यना सबालेंका के 11 डब्ल्यूटीए 1000 खिताबों को पीछे छोड़ दिया है। 2009 में इस फॉर्मेट की शुरुआत के बाद अब स्वियातेक इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। उनसे आगे सिर्फ महान अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स हैं, जिनके नाम 13 डब्ल्यूटीए 1000 खिताब हैं। स्वियातेक का डब्ल्यूटीए फाइनल में रिकॉर्ड भी शानदार हो गया है। वह अब 26 फाइनल में 26 ? नहीं, 26-5 के रिकॉर्ड पर पहुंच गई हैं। 1990 में टियर फॉर्मेट की शुरुआत के बाद 20 या उससे अधिक डब्ल्यूटीए स्तर के फाइनल खेलने वाली खिलाड़ियों में उनका जीत प्रतिशत सबसे बेहतर है।

शानदार रहा पूरा टूर्नामेंट

स्वियातेक ने कनाडियन ओपन में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। उन्होंने पहले मुकाबले में एक सेट 6-0 से जीता और शुरुआती दो मैचों में कुल मिलाकर सिर्फ छह गेम गंवाए। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने मार्ता कोस्त्युक के खिलाफ वापसी करते हुए जीत दर्ज की। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में डायना श्नाइडर को 6-1, 6-2 से हराया। सेमीफाइनल में स्वियातेक ने एलिना स्वितोलिना को तीन सेटों में हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ उन्होंने इसी सीजन में स्वितोलिना के खिलाफ मिली दो तीन-सेट की हार का भी बदला ले लिया।

- निवेदन -

स्वतंत्र बोल से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। फोन और ई-मेल पर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र से घटित कोई घटना, समाचार, या अन्य कोई गतिविधि जो पत्रिका में प्रकाशन योग्य हो.. तो उसे भी भेज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय हिन्दी मासिक पत्रिका तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल और न्यूज वेबसाइट को निर्भीक और जनपक्षीय पत्रकारिता के लिये आर्थिक रूप से सहयोग करें।

बंधन बैंक

बैंक खाता नंबर - 20100031810292
आईएफएससी कोड - BDBL0001958

SB
स्वतंत्र बोल

संपादक स्वतंत्र बोल

डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)

97543-74333, bolswatantra@gmail.com

swatantrabol swatantrabol www.swatantrabol.com हिन्दी मासिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ शासन

सरल सुगम सशक्त

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

प्रशासनिक सुधार

- सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना
- ई-गवर्नेंस को बढ़ावा, ई-ऑफिस प्रणाली
- अटल डैशबोर्ड
- मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप
- सीएम हेल्पलाइन 1076

राजस्व एवं पंजीयन सुधार

- प्रदेश में 119 पंजीयन कार्यालय बन रहे स्मार्ट
- भूमि विवाद रोकने जियो-रेफरेंसिंग
- 10 क्रांतियों और सुगम एप से आसान हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया
- वनाधिकार पट्टा वितरण से मिला मालिकाना हक

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- जन विश्वास 2.0 लागू करने वाला पहला राज्य
- इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ पोर्टल के वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम से त्वरित स्वीकृति
- स्टार्टअप एवं नवाचार नीति 2025-30 लागू
- भारत सरकार द्वारा LEADS 2025 में लैंडलॉक्ड राज्यों में हाई परफॉर्मर की मान्यता

सेवाओं का डिजिटलीकरण

- 6,000+ पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र
- सेवा सेतु से 661 से अधिक सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
- अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सुगम प्रक्रिया

भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं पारदर्शिता

- जेम पोर्टल से सरकारी खरीदी
- भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और नकल के विरुद्ध कठोर कानून
- खनिज ट्रांजिट पास की प्रक्रिया हुई पारदर्शी
- लकड़ी व खनिज ब्लॉक की पारदर्शी ई-नीलामी

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

प्रशासनिक सुधार और नवाचार

प्रगति और समृद्धि का सपना हो रहा साकार

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

RO. No. 13953/55